

संख्या:पी.एल.जी. पीएफ (एफ) 3-7/2020-21 (एसपीबी /एटीआर)
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला -2

प्रेषित

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2
2. सभी उप-कुलपति, विश्वविद्यालय,
हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला-2

२६ मई, 2020

विषय: माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य योजना बोर्ड की दिनांक 17 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक की कार्यवाही।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में राज्य योजना बोर्ड की दिनांक 17 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक की कार्यवाही सलंगन करने का निर्देश हुआ है। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग से सम्बन्धित मर्दों पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट योजना विभाग को भेजने की कृपा करें ताकि उसे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की सूचना एवं जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

2. बैठक की कार्यवाही योजना विभाग की बैबवसाईट <https://planning.hp.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

(अभियुक्त)
(डॉ० बसु सूद)
सलाहकार (योजना)

हिमाचल प्रदेश, शिमला -2
पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि दिनांक शिमला -2 २६ मई, 2020

राज्य योजना बोर्ड की बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है:-

1. राज्य योजना बोर्ड के सभी गैर -सरकारी सदस्य।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला -2
3. निजी सचिव माननीय मन्त्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

4. निजी सचिव मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मानवीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
6. निजी सचिव, प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2
7. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त प्रभागाध्यक्ष, योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश से अनुरोध है कि वे अपने प्रभाग से सम्बन्धित मर्दों पर वांछित कार्यवाही करें।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला -2

हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की 17 फरवरी, 2020 को माननीय मुख्यमन्त्री, हिंप्र० की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार (आर्मसडेल भवन) में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

(बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।)

1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2020 को प्रातः 11 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सभागार में माननीय मुख्यमन्त्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित वार्षिक योजना आकार को अनुमोदित करवाने हेतु आयोजित की गई।
2. सर्वप्रथम सलाहकार (योजना) ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया व बैठक के आयोजन के बारे में अवगत करवाया।
3. इसके पश्चात माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड श्री रमेश चन्द्र धाला ने माननीय मुख्यमन्त्री, राज्य योजना बोर्ड के सदस्यों, प्रशासनिक सचिवों तथा अन्य अधिकारियों का बैठक में स्वागत किया।
4. प्रधान सचिव (योजना) द्वारा वार्षिक योजना 2020-21 के मुख्य बिन्दुओं पर प्रस्तुति (Power Point Presentation) दी गई जिसमें प्रदेश के विकास की वर्तमान स्थिति से सदन को अवगत करवाया गया। इसके अतिरिक्त सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की अन्य प्रदेशों की तुलना में स्थिति का भी व्यौरा दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि वार्षिक योजना की नियोजन प्रक्रिया में सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) अभिन्न अंग रहे हैं तथा इन लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए नई योजनाएँ आरम्भ करने तथा चालू योजनाओं को इन लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए बदलाव किए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने वार्षिक योजना 2020-21 के मुख्य घटकों, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, नाबार्ड तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित परिव्ययों का भी व्यौरा दिया। प्रधान सचिव (योजना) द्वारा राज्य सरकार के समक्ष पेश आ रही वित्तीय एवं विकासात्मक चुनौतियों से भी सदन को अवगत करवाया गया।
5. श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, माननीय जलशक्ति मंत्री ने वर्ष 2014 के बाद नाबार्ड के तहत प्रदेश के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में आबंटित कम राशि पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सभी चुनाव क्षेत्रों में एक समान अनुपात में व्यय करके संतुलन बनाए रखने की बात कही। माननीय सदस्य ने केन्द्र सरकार की भान्ति Medium Irrigation, Major Irrigation तथा Flood Control की ओर विशेष बल देने का सुझाव दिया तथा कहा कि इन योजनाओं पर अधिक से अधिक धनराशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने भारत सरकार को प्रेषित की जाने वाली सभी योजनाओं/परियोजनाओं के लिए राज्य बजट से प्रयुक्त बजट प्रावधान करने की भी बात कही। इसके अतिरिक्त उन्होंने Medium Irrigation तथा

Major Irrigation के अन्तर्गत ऊना जिले में पौंग डैम से पानी उपलब्ध करवाने का सुझाव भी दिया। माननीय सदस्य ने Medium Irrigation के अन्तर्गत Rain Water Harvesting पर एक परियोजना तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित करने की भी बात कही। माननीय सदस्य ने सिंचाई के संसाधनों पर विशेष ध्यान देने तथा बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उचित ढंग से कार्यान्वित करने का सुझाव दिया ताकि प्रदेश में कृषि एवं बागवानी को बल मिल सके।

6. श्री प्रेम सिंह ड्रैक, माननीय गैर-सरकारी सदस्य ने अनुसूचित जाति उपयोजना को लागू करने वाले नोडल विभाग में संस्थागत छां² Manpower Dedicated Staff को और अधिक सुदृढ़ करने का सुझाव दिया। तथा Dedicated Staff को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित अनुसूचित जाति उपयोजना को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत कानून, नियम व अधिनियम बनाने की बात भी कही।

7. श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शिक्षा मंत्री ने भारत सरकार में नीति आयोग की तर्ज पर प्रदेश में भी राज्य योजना बोर्ड का पुर्वगठन करके एक प्रबुद्ध मंडल (Think Tank) स्थापित करने का सुझाव दिया। उन्होंने सतत् विकास लक्ष्यों को आधार बनाकर प्रदेश की प्रगति का अवलोकन/मूल्यांकन करने को कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने नीति आयोग की भान्ति विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों / बुद्धिजीवियों की समितियां गठित करने का सुझाव दिया जिसमें प्रशासनिक सचिव व माननीय मंत्रीगण भी सदस्य हो सकते हैं। उन्होंने इन विशेषज्ञ समितियों से प्राप्त होने वाले सुझावों को आधार बनाकर सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की बात कही। माननीय मंत्री ने हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भी सेवा क्षेत्र (Hospitality, Tourism etc.) को प्राथमिकता देकर उससे प्राप्त होने वाले GST Collection में व्यापक सुधार की संभावनाओं पर काम करने का सुझाव दिया तथा इस क्षेत्र में सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं को प्राथमिकता देकर उन्हें धरातल पर उतारने पर बल दिया। उन्होंने शहरीकरण को दी जाने वाली प्राथमिकता पर प्रश्न उठाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही तथा इन ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सुविधाएं प्रदान करने का सुझाव दिया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों/ बागवानों के साथ-साथ प्रदेश का विकास युनिश्चित किया जा सके। उन्होंने प्रदेश की प्रतिभा पलायन की समस्या पर चिन्ता व्यक्त करते हुए प्रदेश में ही युवाओं को रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध करवाने तथा प्रदेश में विश्व स्तर के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संरथान तैयार करने की बात कही। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत / बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान देने का आहवान भी किया। माननीय सदस्य ने बेरोजगारी की समस्या पर बात करते हुए प्रदेश के युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुपोषण, बौने पन तथा रक्तहीनता जैरी खास्थ्य

२१/५/२०२०

समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश के बाजारों में उच्च पौष्टिक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने तथा प्रदेश की जनता में इन विषयों को लेकर जागरूकता बढ़ाने का भी सुझाव दिया।

8. श्री गोविन्द सिंह, ठाकुर माननीय वन मंत्री ने वन सम्पदा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सदन को अवगत करवाया कि प्रदेश में लगभग 85 लाख करोड़ रुपये की वन सम्पदा उपलब्ध है। प्रदेश में वन आवरण व वृक्ष आवरण को और बढ़ाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। उन्होंने सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वन आवरण को 30 प्रतिशत तक पहुंचाने हेतु प्रदेश में पौधारोपण को 9000 है० से बढ़ाकर 12000 है० तक करने की बात कही तथा इस कार्य हेतु बजट प्रावधान बढ़ाने का भी सुझाव दिया। माननीय सदस्य ने प्रदेश को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली राशि के अतिरिक्त राज्य शीर्ष से भी अधिक बजट उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया, ताकि वन आवरण के लक्ष्यों को समय रहते प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने Silviculture felling के लिए भी समय रहते उपयुक्त बजट उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन को कम पूँजी निवेश मिलने की बात कही है तथा इसे आवश्यकतानुसार बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि आवश्यकतानुसार नई बर्से खरीदी जा सके।
9. श्री अनिल किमटा, माननीय गैर-सरकारी सदस्य ने राज्य योजना बोर्ड की इस बैठक को खाल में दो बार आयोजित करने का सुझाव दिया।
10. श्री परविन्द्र कौशल, उप-कुलपति, हिमाचल प्रदेश वानिकी एवं बागवानी विश्वविधालय, नौणी ने कृषि एवं बागवानी में उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसंधान के क्षेत्र में बजट प्रावधान करने का अनुरोध किया ताकि इस क्षेत्र में नई तकनीकों, बीजों की गुणवत्ता तथा मशीनीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा सके।
11. श्री राजकुमार वर्मा, माननीय गैर-सरकारी सदस्य ने प्रदेश में एक Integrated Sustainable Tourism Policy बनाने का सुझाव दिया जिससे पर्यटन क्षेत्र में कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन में आने वाली रुकावटों को दूर करने हेतु Brain Storming Sessions का आयोजन करके उपयोगी सुझावों से इस क्षेत्र में प्रगति की जा सके। उन्होंने हार्डड्रो पावर नीति पर भी विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया तथा हार्डड्रो पावर को एक उद्योग के तौर पर लेने की बात कही। उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उचित कौशल प्रदान कर पर्यटन तथा हार्डड्रो पावर के क्षेत्र में स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ने की भी बात कही।
12. श्री एस०पी० बंसल, उप-कुलपति, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविधालय, हमीरपुर ने प्रदेश में उपलब्ध अतिरिक्त श्रम शक्ति को प्रशिक्षण प्रदान करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने वार्षिक दस्तावेज में तकनीकी विश्वविधालय को भी दर्शने का आग्रह किया।

इसके अतिरिक्त उन्होंने तकनीकी विश्वविद्यालय को तकनीकी तथा कौशल विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का सुझाव दिया। माननीय सदस्य ने नीति आयोग की तर्ज पर प्रदेश में एक अनुसंधान एवं विकास विभाग बनाने का सुझाव दिया जिससे सरकार को अनुसंधान एवं विकास पर सुझाव प्राप्त हो सके तथा प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने प्रदेश में विशेष पर्यटन क्षेत्र स्थापित करने की बात कही तथा मण्डी जिले में बनाए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हवाला देकर वहीं एक विशेष पर्यटन क्षेत्र बनाने की भी बात कही ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटक आ सकें। इसके साथ-साथ उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में उपलब्ध विकास की संभावना पर कार्य करने को कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के प्रत्येक लक्ष्य पर बनाई जाने वाली समिति को अनुसंधान एवं विकास विभाग से भी जोड़ने का सुझाव दिया।

13. श्रीमति निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक व्याय एवं आधिकारिता) ने वार्षिक योजना दस्तावेज में सतत विकास लक्ष्यों के विषय को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रदेश में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के आधार पर की जाने वाली भर्तियों में अभ्यार्थियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्य, जैसे की सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण तथा अपंगता कल्याण को भी महत्वता दिए जाने की बात कही। इसके अतिरिक्त उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है कि वे ऐसे कौशल विकास के विषय चिन्हांकित करें जो आज के समय अनुसार नए उद्योगों में रोजगार की दृष्टि से उपयोगी हों तथा जिन्हें आई0ठी0आई0 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा सके।
14. श्री रामलाल मारकण्डा, माननीय कृषि मन्त्री ने किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य पर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए कृषि विभाग को मिले कम बजट पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने जनजातीय उप-योजना में की जाने वाली चिन्हांकन को बन्द करने का भी आग्रह किया।
15. श्री बलबीर वर्मा, माननीय गैर-सरकारी सदस्य ने मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना में किए गए कम बजट प्रावधान पर चिन्ता व्यक्त की तथा इसे बढ़ाए जाने का आग्रह किया ताकि प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को रास्तों से जोड़ा जा सके। माननीय सदस्य ने एक नई योजना “मुख्यमंत्री ग्रामीण एम्बुलैंस सङ्कर योजना” चलाए जाने का सुझाव दिया जिससे प्रदेश के सभी गांवों को आवश्यकता के अनुसार एम्बुलैंस सङ्कर सुविधा प्रदान की जा सकें। इसके अतिरिक्त उन्होंने खेल क्षेत्र में एक नई योजना “मुख्यमंत्री खेल मैदान योजना” शुरू करने का सुझाव दिया ताकि प्रदेश के बच्चों को नशे से दूर रखकर खेलों की तरफ आकर्षित किया जा सके जिससे बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य का भी लाभ होगा।

उन्होंने पिछ़ा क्षेत्र उप-योजना में किए जाने वाले बजट प्रावधान को बढ़ाने का सुझाव दिया।

16. प्रो० ए०के० सरियाल, उप-कुलपति, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविधालय, पालमपुर ने प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषि एवं बागवानी में किए जाने वाले अनुसंधान के लिए मिलने वाले बजट (4 से 5 प्रतिशत) को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। उन्होंने कृषि के पैदावार को बढ़ाने के लिए सिंचाई की सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना में भी अनुसंधान के लिए कुछ अतिरिक्त बजट प्रावधान करने का आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही जिसके लिए उन्होंने निरन्तर भर्ती प्रक्रिया को चलाए रखने का सुझाव दिया ताकि प्रदेश के प्रतिभावान् युवाओं को प्रदेश में ही समाहित किया जा सके।
17. श्री मनोज चड्डा, माननीय गैर-सरकारी सदस्य ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र के महत्व को दर्शाते हुए इस क्षेत्र को दिए जाने वाले बजट प्रावधान को अलग से सेक्टरवार प्राथमिकता में दर्शाने का सुझाव दिया। माननीय सदस्य ने आधारभूत संरचना के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन करने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने शहरी विकास के लिए और अधिक बजट प्रावधान करने का सुझाव दिया।
18. कु० प्रज्जवला बरटा, माननीय गैर-सरकारी सदस्य ने प्रदेश के अनछुए क्षेत्रों जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है में आधारभूत संरचना पर विशेष बल देकर पर्यटन विकास का सुझाव दिया। माननीय सदस्य ने प्रदेश की बड़ी परियोजनाओं जैसे कि हाईड्रो पॉवर, हवाई अड्डा निर्माण इत्यादि में स्थानीय निवासियों को निवेश करने के लिए प्रेरित करने को कहा तथा इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व को निवेशकों में बांटने का सुझाव दिया। उन्होंने बैठक में सदस्यों को अवगत करवाया कि किस प्रकार बड़ी-बड़ी कम्पनियां जैसे कि Reebok, Adidas, Nike इत्यादि पर ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करने का दबाव है अतः उन्होंने इन कम्पनियों को कम दर पर हाईड्रो पावर उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रदेश में आने वाले 12 सीटर से अधिक ट्रैम्पों ट्रैवलर पर प्रतिदिन लिए जाने वाले अत्याधिक टैक्स अर्थात् Himachal State Tax/ Permit Charges Rs. 5000/- per day पर चिन्ता व्यक्त की तथा इसे पर्यटक दोस्ताना बनाने के अनुसार इसमें दूसरे प्रदेशों के अनुरूप State Tax/ Permit Charges को कम करने का आग्रह किया ताकि अधिक से अधिक पर्यटक प्रदेश में आ सके।
19. श्री सुखराम चौधरी, माननीय गैर-सरकारी सदस्य ने सिंचाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं में रख-रखाव मद पर उचित बजट प्रावधान करने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रदेश में किसानों द्वारा उगाए जाने वाले अनाज को बेचने के लिए उपयुक्त अनाज मण्डियाँ खोलने की बात कही।

उन्होंने लम्बित पड़ी सिंचाई की परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने का आग्रह किया तथा इस सिंचाई के क्षेत्र के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने को भी कहा। उन्होंने आवार पशुओं व बब्डरों की समस्या के स्थायी समाधान का भी आग्रह किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसानों को गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाने तथा प्रदेश में उचित संचया में पशु चिकित्सालय खोलने का सुझाव दिया है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।

20. श्रीमति सरवीण चौधरी, माननीय शहरी विकास मन्त्री ने नाबार्ड के अन्तर्गत प्रदेश के चुनाव क्षेत्रों में मिलने वाली धनराशि को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया ताकि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने प्रदेश की पिछळी पंचायतों पर नए सिरे से आंकड़े एकत्रित करके उनके मूल्यांकन के पश्चात विकसित हो चुकी पंचायतों के स्थान पर दूसरी पिछळी पंचायतों पर व्यय करने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनुसूचित जाति उप-योजना के अन्तर्गत बनने वाली सङ्कों सम्बन्धित आंकड़ों पर ध्यान देने की बात कही तथा सुझाव दिया कि तैयार सङ्कों को बजट बुक से हटा कर नई सङ्कों को सम्मिलित किया जा सके।

21. प्रो० सिकन्दर, उप-कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कम राजस्व प्राप्ति तथा बढ़ते ऋण की समस्या की बात की तथा इसके निवारण हेतु आर्थिक सलाहकारों को बुलाकर इस पर मंथन करने तथा उपयोगी सुझाव प्राप्त करने का सुझाव दिया।

22. श्री ज्योति कपूर, माननीय गैर -सरकारी सदस्य ने सदस्यों को अवगत करवाया कि किस प्रकार प्रदेश की जलरत के अनुसार विधार्थियों को उचित कौशल प्रदान कर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। उन्होंने विभिन्न रोजगारों में लगे प्रदेश वासियों को समय-समय पर ऑन जॉब प्रशिक्षण करवाने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रदेश में दिए जाने वाले विभिन्न रोजगार अवसरों में कौशलता पर विशेष ध्यान देने तथा उसे शैक्षणिक योग्यता में लेने का सुझाव दिया।

23. श्री रमेश चन्द्र ध्वाला, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड ने प्रदेश में आवश्यकता से अधिक खोले गए स्कूलों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इन स्कूलों के युक्तिकरण करके प्रत्येक पंचायत में एक आर्द्ध स्कूल खोलने का सुझाव दिया तथा प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा पर बल देने को कहा। उन्होंने वन सम्पदा से प्राप्त होने वाले राजस्व पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने एक नई नीति बनाकर चन्द्रन की नर्सरी तैयार कर किसानों को जोड़ने की बात कही ताकि किसानों की आय बढ़ सके तथा इस नीति में इनके उत्पादन तथा बिक्री की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने की बात कही। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों से 50 रुपये प्रति वाहन पर्यावरण सुरक्षा शुल्क लेने का सुझाव दिया तथा प्रदेश में व्यापत आवारा पशुओं की समस्या पर एक कारगर

नीति बनाने की बात भी कही ताकि पशुओं को छोड़ने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जा सके तथा उन पर उचित जुर्माना लगाया जा सके।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश :-

- सर्वप्रथम उन्होंने बैठक में माननीय सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर उनका धन्यावाद किया।
- उन्होंने प्रस्तुति के आधार पर प्रदेश द्वारा विकास के जिन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है उनमें और बेहतर करने तथा जिन क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों से पीछे हैं उनमें बेहतर करने को प्रोत्साहित किया है।
- उन्होंने प्रदेश के सार्वभौमिक विकास पर चर्चा करते हुए प्रदेश में महिला साक्षरता दर, 0-6 वर्ष लिंग अनुपात में आ रही कमी, उचित दर पर न बढ़ रही महिला उत्पादकता दर तथा उन्होंने प्रदेश में कृषि की उत्पादकता, उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने तथा प्राकृतिक खेती को और अधिक प्रोत्साहित करने जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।
- उन्होंने नाबार्ड, सी.आर.एफ जैसे निर्वाचन क्षेत्र वार मिलने वाले बजट तथा उनके द्वारा होने वाले कार्यों का अनुश्रवण करने की बात कही तथा इन मर्दों पर प्राप्त होने वाले बजट को सभी निर्वाचन क्षेत्रों में युक्ति संगत करने का सुझाव दिया ताकि प्रदेश के प्रत्येक गांव को बेहतर सङ्क सुविधा मिल सके।
- उन्होंने माननीय सदस्यों द्वारा पिछळा क्षेत्र उप-योजना में और अधिक धनराशि बढ़ाने के सुझावों पर बात करते हुए सदन को अवगत करवाया कि वर्तमान में इस उप-योजना के अन्तर्गत पिछळी घोषित पंचायतों द्वारा निर्धारित लगभग सभी विकास मानकों को प्राप्त कर लिया गया है परन्तु फिर भी प्राप्त मानकों पर धनराशि खर्च करने के बजाए विकास के नए मानकों को ढूँढ़ कर उन पर धनराशि व्यय करने का सुझाव दिया।
- अन्त में उन्होंने प्रदेश के संस्थानों विशेषकर (Health, Education etc.) के विस्तार पर चर्चा करते हुए इस विषय पर चिन्ता व्यक्त की तथा इन क्षेत्रों में संस्थानों के और अधिक विस्तार करने के बजाए इन क्षेत्रों में गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर देने को कहा।

Annexure - 'क'

List of Participants

Sr. No.	Name	Designation
1	Sh. Mahender Singh	Hon'ble Jal Shakti & Horticulture Minister.
2	Sh. Suresh Bhardwaj	Hon'ble Education & Law Minister.
3	Smt. Sarveen Chaudhary	Hon'ble Urban Development & Town Country Planning Minister.
4	Sh. Ram Lal Markanda	Hon'ble Agriculture, Tribal Development & IT Minister.
5	Sh. Vipin Singh Parmar	Hon'ble Health, Ayurveda & Science & Tec. Minister.
6	Sh. Virender Kanwar	Hon'ble Rural Development, Panchayti Raj & Fisheries Minister.
7	Sh. Bikram Singh	Hon'ble Industries, Labour & Employment & Technical Education Minister.
8	Sh. Govind Singh Thakur	Hon'ble Forest, Transport & Youth Service & Sports Minister.
9	Dr. Rajeev Saizal	Hon'ble Social Justice & Empowerment Minister.
10	Sh. Ram Subhag Singh	Addl. Chief Secy. (Forest/MPP&Power)
11	Smt. Nisha Singh	Addl. Chief Secy. (Printing & Stationery, Labour & Employment, Social Justice & Empowerment & Technical Education)
12	Sh. Sanjay Gupta	Addl. Chief Secy. (Animal Husbandry, RPG & Financial Appeals)
13	Sh. Manoj Kumar	Addl. Chief Secy.(Home &Industries)
14	Sh. R.D. Dhiman	Addl. Chief Secy. (Health & Family Welfare, Personnel ,Tourism & Civil Aviation)
15	Sh. Jagdish Chander Sharma	Principal Secy. (Public Works, Transport & Information Technology)
16	Sh. Kamlesh Kumar Pant	Principal Secy. (Education & Language Art &Culture)
17	Sh. Onkar Chand Sharma	Principal Secy. (Tribal Development, Agriculture & Revenue)
18	Sh. Rajneesh	Secretary (Information & Public relation & Env. Sci. & Technology)
19	Sh. Devesh Kumar	Secretary (GAD/SAD, Parliamentary Affairs and Sainik Welfare)
20	Dr. R.N. Batta	Secretary (Rural Development, Panchyati Raj, Proj. Mon. to Chief Minister & Jal Shakti)
21	Dr. Purnima Chauhan	Secretary (Administrative Reforms, Youth Service &, Sports & Fisheries)
22	Sh. Akshay Sood	Secretary (Cooperation & Housing, Finance, Planning & Economics & Statistics)
23	Sh. G.K. Srivastava	Secretary (Ayurveda, Training & FA)
24	Sh. C. Paulrasu	Secretary (Urban Development & Town & Country Planning)
25	Sh. Amitabh Avasthi	Secretary (Food & Civil Supply & Horticulture)
26	Prof. Pavinder Kaushal	V.C. UHF Nauni University Solan
27	Prof. Ashok K. Sarial	V.C. CSKHPKV, Palampur
28	Prof. S.P. Bansal	V.C. Himachal Pradesh Technical University, Hamirpur

29	Prof. Sikander Kumar	V.C. Himachal Pradesh University, Shimla.
30	Dr. Priyadarshini	Director, Animal Husbandry Department
31	Dr. A.K. Gupta	Director, Health & Family Welfare Department
32	Sh. Ram Kumar Gautam	Director, Urban Development Department
33	Smt. Sushma Watts	Addl. Director., Women and Child Development Department
34	Sh. Devinder Kumar	S.N.O, Ayushman Bharat, Health Department
35	Sh. Pardeep Chauhan	Project Director
36	Sh. Manohar Lal	Deputy General Manager, NABARD
37	Sh. Ganesh	Addl. General Manager, NABARD
38	Sh. Anil Saunkhala	Deputy Resident Director, PHD Chamber of Commerce
39	Dr. Gopal Beri	Deputy M.D. N.H.M.
40	Smt. Sunita Kapta	Addl. Controller, Store
41	Sh. Dalip Sharma	Deputy Controller, Health Department
42	Sh. Govind Rai	Jt. Controller (F&A), National Health Mission
43	Dr. Seema Chahal	Addl. Director, Animal Husbandry Department
44	Sh. Chander Shekhar Sewal	Jt. Controller, Higher Education
45	Sh. K. S. Thakur	APCCF(CAMPA), Forest Department
46	Sh. Dalip Sharma	Dy. Controller Health
47	Sh. Dalip Sharma	Dy. Controller (F&A), Health Department
48	Sh. Ram Sawroop	Hon'ble Member of Parliament, Non official Member
49	Sh. Sukh Ram Chaudhary	Hon'ble M.L.A, Paonta Sahib, Non official Member
50	Sh. Rakesh Jamwal	Hon'ble M.L.A, Sundernagar, Non official Member
51	Sh. Vinod Kumar	Hon'ble M.L.A, Nachan, Non official Member
52	Sh. Surender Sauri	Hon'ble M.L.A, Banjar, Non official Member
53	Sh. Narinder Thakur	Hon'ble M.L.A, Hamirpur, Non official Member
54	Sh. Balbir Verma	Hon'ble M.L.A, Chopal, Non official Member
55	Sh. Govind Ram Sharma	Non official Member
56	Sh. P.S. Draik	Non official Member
57	Sh. Yuvraj Bodh	Non official Member
58	Sh. K.S. Rana	
59	Sh. R.K. Kondal	DAHP
60	Brig. Khushal Thakur	Non official Member
61	Sh. Jyoti Kapoor	Non official Member
62	Dr. Seema Chahal	Additional Director, Animal Husbandry
63	Smt. Reetu Sethi	Non official Member
64	Smt. Veena Thakur	Non official Member
65	Sh. Manoj Chhadha	Non official Member
66	Sh. Anil Kimta	Non official Member
67	Ms. Prajwal Busta	Non official Member
68	Sh. Raj Kumar Verma	Non official Member
69	Sh. Prabodh Saxena	Pr. Secretary (Planning/Finance)
70	Dr. Basu Sood	Adviser (Planning)
71	Sh. Surender Paul	Joint Director (Planning)
72	Sh. Ravinder Kumar	Dy. Director (Planning)
73	Sh. Ravi Chand Negi	Dy. Director (Planning)
74	Sh. Anuj Kumar	Dy. Director (Planning)
75	Smt. Sunita Walia	Research Officer (Planning)
76	Sh. Naresh Sharma	Research Officer (Planning)

77	Sh. Sanjeev Sood	Research Officer (Planning)
78	Sh. Desh Raj	Research Officer (Planning)
79	Sh. Vickrant Joshi	Research Officer (Planning)
80	Sh. Dinesh Sharma	Programme Planning Officer (Planning)
81	Sh. Rajiv Sangrai	Research Officer (Planning)
82	Smt. Suman Negi	Research Officer (Planning)
81	Sh. Ajmer Singh	P.A.(Planning)
82	Sh. Rakesh Gautam	Statistical Assistant (Planning)
83	Sh. Inder Dutt	Computer (Planning)
84	Km. Manisha	Steno.(Planning)